कविता

सूरज को नहीं डूबने दूंगा

– (साभार: कविता कोश)

अब मैं सूरज को नहीं डूबने दूंगा।
देखो मैंने कंधे चौड़े कर लिये हैं
मुट्ठियां मजबूत कर ली हैं
और ढलान पर एड़ियां जमाकर
खड़ा होना
मैंने सीख लिया है।
घबराओ मत
मैं क्षितिज पर जा रहा हूं।
सूरज ठीक जब पहाड़ी से लुढकने लगेगा
मैं कंधे अड़ा दूंगा
देखना वह वहीं ठहरा
होगा।
अब मैं सूरज को नहीं डूबने दूंगा।
मैंने सुना है उसके रथ में तुम हो
तुम्हें मैं उतार लाना चाहता हूं
तुम जो स्वाधीनता की प्रतिमा हो
तुम जो साहस की मूर्ति हो
तुम जो धरती का सुख हो
तुम जो कालातीत प्यार हो
तुम जो मेरी धमनी का प्रवाह हो
तुम जो मेरी चेतना का विस्तार हो
तुम्हें मैं उस रथ से उतार लाना चाहता हूं।
रथ के घोड़े
आग उगलते रहें
अब पहिये टस से मस नहीं होंगे
मैंने अपने कंधे चौड़े कर लिये हैं।

कौन रोकेगा तुम्हें
मैंने धरती बड़ी कर ली है
अन्न की सुनहरी बालियों से
मैं तुम्हें सजाऊंगा
मैंने सीना खोल लिया है
प्यार के गीतों में मैं तुम्हें गाऊंगा
मैंने दृष्टि बड़ी कर ली है
हर आंखों में तुम्हें सपनों सा फहराऊंगा

सूरज जायेगा भी तो कहां
उसे यहीं रहना होगा
यहीं हमारी सांसों में हमारी रगों में
हमारे संकल्पों में
हमारे रतजगों में
तुम उदास मत होओ
अब मैं किसी भी सूरज को
नहीं डूबने दूंगा।

चिकित्सा सेवा या मौत के सौदागर

सबसे ज्यादा कर देने वाली मेहनतकश जनता आज अपनी कमाई का अधिकतम हिस्सा महंगी दवा और महंगे इलाज पर खर्च करने के बावजूद बहुत ही खराब जिन्दगी जीने के लिए मजबूर है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के सर्वेक्षण के मुताबिक हमारे देश की जनता अपनी चिकित्सा और स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च का 40 फीसदी सिर्फ दवाओं पर खर्च करती है। 65 फीसदी लोग नियमित रूप से जरूरी दवाएं लेने में असमर्थ हैं। 40 फीसदी से भी अधिक लोग़ों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए पैसे उधार लेने पड़ते हैं या अपने गहने और घर का अन्य सामान बेचना या गिरवी रखना पड़ता है।

एक बार अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने के बाद 35 फीसदी लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। गरीब लोग़ों का कर्ज में डूबे होने का एक बड़ा कारण बीमारियों में दवाइयों पर होने वाला खर्च भी है। इसके अलावा 33 फीसदी आबादी आर्थिक तंगी के चलते बीमार होते हुए भी फीस न होने के कारण डॉक्टर को दिखा भी नहीं पाती है।

अधिकांश आबादी की खराब आर्थिक स्थिति के बावजूद स्वास्थ्य और चिकित्सा के ऊपर देशभर में खर्च होने वाली कुल धनराशि का केन्द्र सरकार से सिर्फ 4 प्रतिशत, राज्य सरकारों से 14 प्रतिशत, निजी निवेश से मात्र 2.9 प्रतिशत और निजी बीमा क्षेत्र से 0.1 प्रतिशत प्राप्त होता है। इसके बावजूद आज देश की जनता को पर्याप्त इलाज नहीं मिल पा रहा है।

हमारे देश में निजी दवा निर्माता कम्पनियों, सरकारी और निजी डॉक्टरों तथा सरकार की मिलीभगत से चिकित्सा क्षेत्र मानव सेवा की जगह मानव बाजार का रूप ले चुका है। एक ही रसायन से बननेवाली अलग-अलग कम्पनियों की दवाओं की कीमतों में ज़मीन-आसमान का फर्क होता है। जबकि उसी रसायन की जेनरिक दवा काफ़ी सस्ती होती है। उदाहरण के तौर पर एक दर्द निवारक रसायन निमुसलाइड है, जिसे नॉनप्रोप्राइटरी या जेनरिक नाम से जाना जाता है और इसी साल्ट की निसीप निमलिन, निमुलिड जैसी दवा अलग-अलग कम्पनियां अपने-अपने ब्रांड नाम से बेचती हैं।

जेनरिक और ब्रॉडिड दवाओं की कीमत में फर्क दो-चार या दस गुने का ही नहीं बल्कि पचास गुने तक होता है। जैसे तमिलनाडु मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन द्वारा सरकारी टेंडर से खरीद की जाने वाली एलबेंडाजोल नामक गोली जो बाजार में 12 रुपये में मिलती है, उसे फैक्ट्री से केवल 35 पैसे में खरीदा जाता है। इसी तरह एल्प्राजोल्म साल्ट की दवा जो बाजार में रेस्टीब्रॉड नाम से 24 रुपये 75 पैसे की एक गोली बिकती है उसे केवल 41 पैसे प्रति गोली की दर से खरीदा जाता है।

एक ही तरह की दवाओं के दो तरह से दाम कैसे हो सकते हैं। सरकार के लिये कुछ और बाजार में आम जनता के लिये कुछ और। क्या सरकार को दी जानेवाली उसी दवा में लागत कम आती है और बाजार में बेचने पर ज्यादा खर्च आता है? अगर नहीं, तो फ़िर इतना अंतर क्यों है? जरूरी दवाएं क्यों आम जनता की पहुंच से दूर हो गयी हैं? इन ब्रांडेड दवाओं की कीमत ज्यादा होने की पहली वजह है, अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर दवा कमपनियों का एकाधिकार होना और दवा मूल्य नियंत्रण कानून बनने के बाद भी सरकार द्वारा उसे प्रभावी तरीके से लागू न करना। सरकार इन देशी-विदेशी दवा कम्पनियों के प्रति उदार रुख अख्तियार करती है। दूसरी वजह सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों के चिकित्सकों की इन दवा कम्पनियों के साथ साँठ-गांठ, जिसके चलते ये डॉक्टर सस्ती जेनरिक दवाओं के बदले उसी साल्टमहंगी ब्रांडेड दवाएं लिखते हैं जिसे भोले-भाले मरीज़ों को खरीदना पड़ता है। गरीब जनता की बीमारी ठीक हो न हो उस परिवार को ऐसी बीमारी लग जाती है जिससे छुटकारा मिलना मुश्किल होता है। अपनी लूट को जारी रखने के लिए ये ब्रांडेड दवा कम्पनियां सरकारी और निजी डॉक्टरों को इन गरीब मरीज़ों की जिन्दगी की कीमत पर महंगे तोहफे देती हैं और विदेशों की सैर कराती हैं।

अजीब है कि जिन्दगी देने वाले ही आज के मौत सौदागर हो गये हैं। सरकार की नीतियां सबको स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने की जगह कुछ देशी-विदेशी मल्टी ब्रांडेड कम्पनियों, निजी चिकित्सकों और निजी अस्पतालों के मालिकों के स्वार्थों की पूर्ति करती है। क्या सरकार इन सरकारी और निजी डॉक्टरों और इन मल्टी ब्रांडेड कम्पनियों की लूट पर लगाम नहीं लगा सकती? अगर इन कालाबाजारियों द्वारा जनता की लूट को रोका नहीं गया तो हमें यह सोचना होगा कि सरकार को जनता के स्वास्थ्य और उसकी जान की कितनी परवाह है। अपने अधिकारों के प्रति सजग और एकजुट होकर चिकित्सा सेवा जैसी बुनियादी जरूरत के लिए संघर्ष करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।

-देश-विदेश

गडकरी कृष्णपाल का जादू

पेज एक का शेष

में कितनी जटिल व समय खपाऊ होती है। इन सब हालात के बावजूद गडकरी शिलान्यास भाषण में फ़र्माते हैं कि पुल डेढ साल में बन कर तैयार हो जायेगा। इतने समय में तो यदि डी पी आर तथा ज़मीन अधिग्रहण का काम ही पूरा हो जाय तो बहुत बड़ी बात है। बदरपुर बार्डर से कैली गांव तक बनने वाला बाईपास गत 25 वर्षों से निर्माणाधीन चल रहा है लेकिन रेलवे ओवर ब्रिज के निकट की ज़मीन अभी तक अधिग्रहीत नहीं हो पाई है। इसी तरह मैट्रो रेल वाले अपना काम पूरा करने के कगार पर है लेकिन सरकार की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हुई है इसके चलते मैट्रो रेल भी समय सीमा में तैयार नहीं होने जा रही।

दूसरा बड़ा झूठ गडकरी ने यह बोला कि निर्माण कार्य पर खर्च होने वाला 200 करोड़ उनकी केन्द्र सरकार वहन करेगी। सरकार एक पैसा भी वहन करने नहीं जा रही। यह सारा पैसा बल्कि इससे कई गुणा अधिक पैसा वह कम्पनी जनता से टोल टैक्स के जरिये वसूलेगी जो इसका निर्माण करेगी। हां ठेका प्राप्त करने के एवज में वह कम्पनी गडकरी व कृष्णपाल को जरूर मोटी भेंट चढायेगी।

दरअसल चुनाव की इस बेला में स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मन्त्री कृष्णपाल के लिये यह नौटंकी करनी बहुत ही जरूरी थी। उनके जिम्मे इलाके की 9 में से 9 विधान सभा सीटें भाजपा को दिलाना है। तिगांव विधान सभा क्षेत्र जहां से वे अभी तक विधायक थे और जिसमें यह पुल भी पड़ता है, से वे अपने बेटे को चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। इसी नौटंकी की बदौलत मुफ़्त में भारी जनसभा हो पाई। टिकट पाने की होड़ में एक से बढ कर एक उम्मीदवार अपने खर्चे पर बसों, ट्रलियों व कारों आदि में भीड़ ढोकर लाये, इसी को तो कहते हैं हींग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा होय।

यूं गडकरी ने वाहवाही लूटने के लिये यानी सिर पर खड़े विधानसभा चुनावों में वोटरों को उल्लू बनाने के लिये यह घोषणा भी कर दी है कि जब तक सड़कें व पुल पूरी तरह से बनकर तैयार न हो जायें तब तक उन पर टोल टैक्स नहीं वसूला जायेगा। पर आज के दिन हर आधी-अधूरी/निर्माणाधीन सड़क पर भारी भरकम टोल टैक्स वसूली बदस्तूर जारी है। चुनाव के बाद तो गडकरी को अपनी यह घोषणा कभी भूले से भी याद नहीं आयेगी।

भाजपा टिकट कांऊटर पर धन बल सबसे प्रबल

पेज एक का शेष

इनकी आवासीय इमारतों में प्राय: जज तथा सरकारी अधिकारी रहते हैं। इसके चलते गोयल को उनसे 'मधुर' सम्बन्ध विकसित करने में काफ़ी सुविधा रहती है। इन्हीं 'मधुर' सम्बन्धों के आधार पर वे इनसे खासे काम निकलवाते रहते हैं।

अपने सम्बन्धों को और प्रगाढ करने के लिये गोयल अक्सर बहुत ही हसीन व रंगीन दावतों का आयोजन भी करते रहते हैं। इनमें विदेशी शराब के अलावा देशी विदेशी शबाब भी रहता है। ज़्यादा ही अन्तरंग अफ़सरों की सेवा के लिये इनके पास पंचतारा होटल में सर्विस एपार्टमेंट भी हैं। अति सुरक्षित एवं विलासितापूर्ण इन अपार्टमेंटों में पधारने वाले वी वी आई पी मेहमानों की तमाम तरह की फ़रमाइशें पूरी करने का इन्तज़ाम रहता है।

बीते लोकसभा चुनाव में कृष्णपाल के फंड मैनेजमेंट का सारा दायित्व इन्हीं के पास था। किस से क्या लेना है और किसको क्या देना है, यह सब गोयल के ज़िम्मे ही था। भीतरी जानकारी रखने वाले बताते हैं कि गोयल कृष्णपाल का बिजनेस पार्टनर भी है। कृष्णपाल का पैसा (काला या सफ़ेद) कहां लगाना है, कहां नहीं और कैसे लगाना है यह सब गोयल के जिम्मे ही रहता है।

इस प्रकार सत्ता की दलाली के द्वारा कमाये धन के बल पर धनपशु बने गोयल ने उन सभी छोटे-बड़े भाजपाइयों को पीछे धकेल दिया है जो बरसों से भाजपाई कमल को सींच रहे थे। दरअसल भाजपा में ऐसे गोयलों की जरूरत तो हमेशा ही रही है। वाजपेयी को प्रमोद महाजन की तो मोदी को पीयूष गोयल की। ऐसे में कृष्णपाल को भी तो विपुल गोयल की जरूरत होना अनिवार्य है। स्थानीय लोग बखूबी जानते हैं कि विपुल के पिता रोहतास गोयल एक मामूली डिपु होल्डर थे। सभी जानते हैं कि डिपु होल्डर का असली धंधा चीनी व तेल इत्यादि को बलैक में बेचना होता है। इसके लिये जरूरी है कि संबन्धित अधिकारियों को रिश्वत दी जाय। घर से ही काला बजारी व रिश्वत देने की कला में महारत हासिल करने के बाद विपुल गोयल ने जमकर इस कला का इस्तेमाल किया। सत्ता चाहे चौटालों की हो या भूपेन्द्रों की या मोदीयों की, विपुल का सीक्का हर राज में फ़र्राटे से चलता है।

बेशक बी जे पी ने अभी टिकट की घोषणा नहीं की है परन्तु विपुल ने अपना चुनाव अभियान पूरी गति से शुरू कर दिया है। करीब 500 छोटे-बड़े होर्डिंग 27 अगस्त तक क्षेत्र में लग चुके थे। करीब 25000 टी शर्ट बन कर आ गयी हैं जिन पर विपुल, कृष्णपाल, गडकरी, मोदी आदि की तस्वीर छपी है। इसी तरह की एक टी शर्ट पहने एक रिक्शा चालक से जब इस संवाददाता ने कहा कि भाई टी शर्ट तो बड़ी शानदार है, कितने की ली? ''अजी साब यें तो मुफ्त में बंट रही हैं वोटों के लिये।'' तो फ़िर तो तुम वोट भी इसी को दोगे? ''मुझे पता ही नहीं कि यह कौन सी पार्टी की है, फिर भी वोट तो हम सोच समझ कर ही देंगे।''

कुछ इसी तरह की बात ओल्ड फ़रीदाबाद में उस नाई से सुनने को मिली जिससे इस संवाददाता ने कटिंग कराई। पूछने पर नाई ने कहा, ''अजी कोई टी शर्टों से वोट दिये जाते हैं, वोट के लिये तो हम सब मिल बैठकर तय करेंगे।''

विपुल अपनी टिकट पक्की माने भी क्यों नहीं जब गडकरी उसके यहां खाना खा कर जाये बाबा रामदेव उसके घर पर आकर आसन लगाये, अमितशाह उसके दरवाजे पर आये, फ़िर कृष्णपाल तो अपने घर का ही है तो टिकट मिलने में क्या दिक्कत हो सकती है? कोई नहीं, वह तो मिली पड़ी है बस घोषणा होनी बाकी है,वह भी हो ही जायेगी देर-सबेर।

मज़दूर मोर्चा

नियमित रूप से हर माह की पहली व सोलह तारीख को प्राप्त करने के लिए अपने हॉकर से संपर्क करें। कोई दिक्कत होने पर फ़रीदाबाद के पाठक शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर तथा बल्लभगढ़ के पाठक अरोड़ा न्यूज़ एजेन्सी फोन नं 9811477204, करनाल के पाठक अशोक कुमार जैन, फुटवियर जवाहर मार्किट सदर बाजार से फोन नं 9896436739 पर सम्पर्ककरें।